सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

सफलता की कुंजी

ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी ब्राइट बनाता है।

अनमोल विचार

कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस वक्त वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

-चाणक्य

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 23 JANUARY TO 29 JANUARY 2020 • VOLUME-22 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

पाक की तरह धर्मशासित देश कभी नहीं बना भारत, भारतीय मूल्यों में सभी धर्म हैं बराबर-राजनाथ

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारतीय मूल्यों में सभी धर्मों को बराबर माना जाता है और यही वजह है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और यह पाकिस्तान की तरह धर्मशासित देश कभी नहीं बना। दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शिविर में रक्षा मंत्री ने कहा, ''हम (भारत) कहते हैं कि हम धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारा पड़ोसी देश तो यह ऐलान कर चुका है कि उनका एक धर्म है। उन्होंने खुद को धर्मशासित देश घोषित किया है। हमने ऐसी घोषणा नहीं की है।''

सिंह ने कहा, ''यहां तक कि अमेरिका भी धर्मशासित देश है। भारत एक धर्मशासित देश नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साधु-संतों ने न केवल हमारी सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का हिस्सा माना बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों को उन्होंने एक परिवार बताया।''

सिंह ने रेखांकित किया कि भारत ने कभी भी यह घोषणा नहीं की कि उसका धर्म हिंदू, सिख या बौद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग यहां रह सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, ''उन्होंने 'वसुधैव कुटुंबकम' की उक्ति दी जिसका मतलब है कि पूरा विश्व एक परिवार है। पूरे विश्व में यह संदेश यहां से ही गया।''

मुंबई वालों के लिए खुशखबरी, अब चौबीसों घंटे खुली रहेंगी दुकानें और मॉल

■ मुंबई/ब्यूरो

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को ''मुंबई में मॉल, सिनेमाघर और दुकानों को 24 घंटे खोलने की नीति को मंजूरी दी। नयी नीति 27 जनवरी लागू से होगी। लंदन की पांच अरब पाउंड की रात की अर्थव्यवस्था को रेखांकित करते हुए पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि सरकार के इस फैसले से राजस्व और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस समय मुंबई के सेवा क्षेत्र में पांच लाख लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉल और खाने-पीने की दुकानों को रात को खोलना बाध्यकारी नहीं है। ठाकरे ने कहा, '' जो लोग मानते हैं कि पूरी रात प्रतिष्ठानों को खोले रखने से बेहतर कारोबार होगा, वे ही इसपर अमल करेंगे।'' राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक पहले चरण में दुकानों, रेस्तरां, गैर आवासीय इलाकों में स्थित मॉल तथा मिल परिसरों के थियेटर को पूरी रात खोलने की अनुमति होगी। शिवसेना नेता ने कहा, ''बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और एनसीपीए के नजदीक नरीमन प्वाइंट की सड़क पर सचल खाने की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी और खाद्य निरीक्षक उनपर नजर रखेंगे। अगर ठोस कचरा प्रबंधन, आवाज की सीमा और कानून व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन हुआ तो, उन पर आजीवन प्रतिबंध का प्रावधान है।'' उन्होंने कहा कि पुलिस पर यह दबाव नहीं होगा कि वे देर रात डेढ बजे यह सुनिश्चित करें कि दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हैं। इसे भी पढ़ें- ष्ट विरोध प्रदर्शनों पर बोले योगी, पैसा लेकर आगजनी की घटनाओं को दिया जा रहा अंजाम राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने कहा, ''इसके बजाय अब वे कानून व्यवस्था कायम रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।''

स्वयंभू बाबा नित्यानंद की बढ़ी मुश्किलें, इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया

■ अहमदाबाद/ब्यूरो

इंटरपोल ने स्वयंभू बाबा नित्यानंद का पता लगाने में मदद करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गुजरात पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। कर्नाटक में नित्यानंद के खिलाफ बलात्कार का एक मामला दर्ज किये जाने के बाद पिछले वर्ष वह भारत से भाग गया था।

राज्य पुलिस ने यहां नित्यानंद के आश्रम से दो लड़कियों के लापता होने के बाद पिछले वर्ष नवम्बर में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत में दायर एक आरोप पत्र में इस कदम का खुलासा किया है। पुलिस उपाधीक्षक के टी कामरिया ने कहा, ''इंटरपोल ने इस महीने विवादास्पद स्वयंभू बाबा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।'' पुलिस ने बताया कि वे इस पर काम कर रहे थे कि अब उसके खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। एक आपराधिक जांच के सिलसिले में एक व्यक्ति का पता लगाने या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है जबकि रेड कॉर्नर नोटिस एक वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है।

सेंसेक्स 208 अंक टूटा, ONGC में पांच प्रतिशत से अधिक का नुकसान

■ मुंबई/ब्यूरो

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स बुधवार को शुरुआती लाभ गंवाकर 208 अंक टूटकर बंद हुआ। ऊर्जा,बिजली, वाहन और वित्तीय कंपनियों के शेयर दबाव में रहे। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन के उच्चस्तर से फिसलकर 473 अंक तक के नुकसान में आ गया था। अंत में सेंसेक्स 208.43 अंक या 0.50 प्रतिशत के नुकसान से 41,115.38 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसने 41,532.29 अंक का उच्चस्तर और 41,059.04 अंक का निचला स्तर छुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 62.95 अंक या 0.52 प्रतिशत के नुकसान से 12,106.90 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में ओएनजीसी का शेयर सबसे अधिक 5.13 प्रतिशत टूटा। इसके बाद एनटीपीसी, मारुति, कोटक बैंक, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं दूसरी ओर नेस्ले इंडिया, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एसबीआई और भारती एयरटेल के शेयर 1.86 प्रतिशत तक चढ़ गए। विश्लेषकों का कहना है कि आम बजट से पहले ज्यादातर बड़े शेयर बिकवाली दबाव के चलते 'सुधार' प्रक्रिया में है। इसके अलावा वैश्विक एजेंसियों द्वारा भारत के वृद्धि अनुमान को घटाने और कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद के अनुकूल नहीं रहने की वजह से भी घरेलू निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है।

अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्की और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार भी लाभ में रहे।

नारी समर्थ है उत्पीड़न रोकने हेतु

- विजय कुमार

आये दिन बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं के लिए किसे उत्तरदायी कहा जाये उसके लिये चिन्तन आवश्यक है हालांकि हम उसके लिये सर्व प्रथम सरकार को ही दोषी ठहराते है चूंकि सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिये राष्ट्र की सुरक्षा और जन सुरक्षा के कानून बनाते समय वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिये जो प्राय होती रही है और हो भी रही है जो भारत और भारतीयों के लिए घातक सिद्व हो रही है।

ऐसी दुखद दुर्घटनाओं के लिए केवल सत्ता पक्ष नहीं संसद में बैठने वाले प्रत्येक नेता उत्तरदायी है।

रेप और मर्डर के विरूद्व बनने वाले कड़े कानून का समर्थन प्रत्येक सांसद को करना चाहिए पर कुछ नेता अपनी वोट की नीति को लेकर ऐसे वकत्वय देते हैं कि मानवता शर्म सार होती है परन्तु ब्यान देने वाला नेता स्वंय को महान समझता है धिक्कार ऐसे नेताओं पर हैदराबाद की दुर्घटना पर एक नेत्री ने कहा कि दोषियों को न्याय मिलना चाहिए वे निहत्थे थे जो पुलिस द्वारा मार दिये गए इस देश में क्या पुलिस को सुरक्षा का अधिकार नहीं।

उन पर अगर हमला हो तो वह कार्यवाही न करें ऐसा सैनिकों के प्रति ब्यान था। एक नेता का कितने सुरक्षा कर्मियों की बलि देना चाहेंगें ये नेता क्या जिस महिला के साथ यह दुर्घटना हुई उसके हाथ में ए.के.47 थी ?

उस 8 साल की बच्ची के साथ जो हुआ उसके लिये क्या कहेंगी

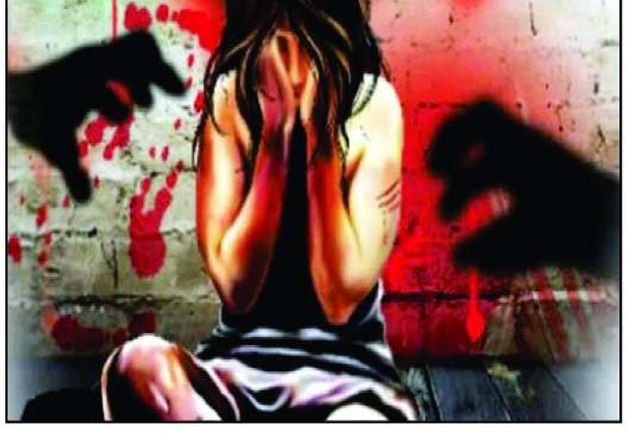

यह जानवरों के प्रति प्रेम रखने वाली नेत्री क्यूं शर्म नहीं आती ऐसे नेताओं को देश की जनता अब जागृत हो चुकी है सरकार में रहते कई नेता जो मन्त्रालय विहीन हो जाते है तो ऐसे ब्यान देने लगते है निजी हितों को जब तक समाज और समाज का नेतृत्व करने वाले नहीं त्यागें गए तब तक दुर्घटनायें होती रहेंगी। क्या कानून बनाने वाले उसका पालन करवाने वाले, न्याय देने वाले बलात्कार करने वालों के घर में महिलाएं नहीं है बेटियां और बहने नहीं है पत्नीयां नहीं है भाव यह कि महिला हर जगह मौजूद है वह हर पत्नी जिसका पति, वह हर मां जिसका बेटा है, वह हर बहन जिसका भाई है, वह हर बेटी जिनके पिता है उन्हें प्रण लेना होगा कि वह अपने पति, पिता, पुत्र, भाई को विवश करें कि वह ऐसी दुखद दुर्घटनाओं को न करें न होने दें और न उनका समर्थन करें महिलाओं में ही यह अदभुत शक्ति है कि वह ऐसी दुर्घटनाओं को रोक सकती है। तीसरा उत्तरदायी यही है आदि शक्ति सबला नारी।

वोट की राजनीति का शिकार बना रामामण्डी फ्लाई ओवर

पुल और फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण से हो सकता है बड़ा हादसा

गत दिनों टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग मीटिंग में जिलाधीश अधिकारियों को निर्देश देते हुए।

■ जालंधर से प्रभात सूरी की विशेष रिपोर्ट

गत दिनों जिलाधीश जालंधर द्वारा टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों से मीटिंग को सम्बोधित करते हुए भविष्य के लिए विकासोन्मुखी योजनाओं का सृजन करने हेतु आशा प्रकट की परन्तु खेद इस बात का है कि भविष्य तो गत 70 वर्षों से जनता देखती आ रही है परन्तु क्या भूत का भविष्य वर्तमान नहीं। मेरा जिला प्रशासन से विनम्र यह निवेदन है कि वर्तमान को सुखद बनाये और वर्तमान में हो रहे अतिक्रमण को रोकने का प्रयास करें जिसके कारण भविष्य दुखद हो रहा है कई बार सूचनाओं और समाचार पत्रों द्वारा रामामण्डी फ्लाई ओवर के नीचे और अब तो साथ लगते कैंटबोर्ड के क्षेत्र प्राईमरी स्कूल की सड़क पर मलवा डालकर स्कूटर स्टैंड , पार्किंग और अब 16 नई दुकानों का निर्माण किया जा चुका है।

सड़क तो पहले ही 10 फुट बची है अतिक्रमण के परिणामस्वरूप और शेष बची सड़क पर दुकानें बनने से क्या आम नागरिक एवं स्कूली विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं आयेगी जहाँ इस सड़क पर कैन्टबोर्ड द्वारा कूड़ा इकट्ठा करने का डम्प बनाया गया है, उसके सामने खाने की दुकान जो लगभग 80 गज दूरी पर है यहां तो धार्मिक स्थल भी बन चुका है जो भविष्य में प्रशासन के लिए सिरदर्द बन सकता है कम से कम प्रशासन तो वोट की राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें हमारा जिला प्रशासन से पुन: आग्रह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नागरिक हितों के दृष्टिगत उन नाजायज हो रहे कब्जों पर यथोचित कार्यवाही करें तभी भविष्य के लिए विकासोन्मुखी योजनाओं का लाभ जनता को मिल सकेगा। केवल योजनायें न बनाकर पिछली योजनाओं को कार्यनवित करें।

अंकित

जो इंसान अपने स्वार्थों को सर्वोपरि मानता है, वह एक ऐसी अंधेरी रात में जी रहा है, जिसमें चांद और तारे तक नहीं होते। सघन अंधकार ही ऐसे इंसान की नियति होती है।

■ चार्वाक

www.jalandharbreeze.com

साप्ताहिक
23 जनवरी से 29 जनवरी 2020
जालंधर ब्रीज

दखल

उच्च शिक्षा में दिख रहा है सुधार

उच्च शिक्षा में भारत की स्थिति सुधरी है और रैंकिंग धारक इन भारतीय संस्थानों ने उभरती अर्थव्यवस्था के बीच वैश्विक स्तर पर अपार क्षमता का प्रदर्शन किया है। गौर करें तो वैश्विक जगत के मामले में भारत की रैंकिंग अब भी काफी कमजोर है। हालांकि, अब भी उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। मसलन शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना होगा। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के साथ संस्थानों को आवश्यक संसाधन मुहैया कराने होंगे। तब भारत और भी समृद्ध हो जाएगा।

यह शुभ संकेत है कि उच्च शिक्षा के मामले में दुनिया में भारत की स्थिति अब पहले से बेहतर हुई है। लंदन स्थित एक वैश्विक संगठन टाइम्स हायर एजुकेशन की हाल ही में जारी इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के 49 संस्थानों ने जगह बनाई है। 2018 में यह संख्या 42 थी। रैंकिंग पर नजर डालें तो सूची में शीर्ष 200 संस्थानों में भी भारतीय विश्वविद्यालय बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं और 2018 के 17 संस्थानों से बढ़कर यह संख्या 25 हो गई है। इस रैंकिंग में 14वें पायदान पर भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी बेंगलुरु भारत में शीर्ष पर है। इसी तरह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 27वें स्थान पर है, लेकिन गौर करें तो यह दोनों ही संस्थान इस वर्ष की रैंकिंग में एक पायदान नीचे खिसके हैं। यानी रैंकिंग गिरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईआईटी रुड़की 21 पायदान की छलांग लगाते हुए पहली बार 35वें स्थान पर पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) और एमिटी यूनिवर्सिटी भी इस वर्ष शीर्ष 150 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे और आईआईटी हैदराबाद पहली बार शीर्ष 150 संस्थानों में शामिल हुए हैं।

निःसंदेह उच्च शिक्षा में भारत की स्थिति सुधरी है और रैंकिंग धारक इन भारतीय संस्थानों ने उभरती अर्थव्यवस्था के बीच वैश्विक स्तर पर अपार क्षमता का प्रदर्शन किया है। गौर करें तो वैश्विक जगत के मामले में भारत की रैंकिंग अब भी काफी कमजोर है। इसे समझने के लिए रैंकिंग पर दृष्टिपात करें तो वैश्विक स्तर पर चीन की शिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पायदान पर है। सूची में चीन के सबसे अधिक 72 संस्थान रैंकिंग में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। चीन की ही पीकिंग यूनिवर्सिटी व जिहांग यूनिवर्सिटी दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यूनिवर्सिट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफचाइना चौथे व मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पांचवे पायदान पर है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि भारत में उच्च शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार की जरुरत है। अच्छी बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में ठोस प्रयास जारी है। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक है कि सकल दाखिला अनुपात बढ़ाने के साथ रिक्त पड़े पदों को भरा जाए और उच्च शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए।

यह सही है कि उच्च शैक्षिक संस्थानों को आधुनिकता से लैस किए बिना बेहतर उत्पाद हासिल नहीं किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 'उच्च एवं तकनीकी शिक्षा आंकड़े' पर गौर करें तो उच्च शिक्षा में छात्रों का सकल दाखिला अनुपात 18 से 23 वर्ष की आबादी में महज 20 फीसद के आसपास है जो कि वैश्विक लिहाज से बहुत कम है। गत वर्ष यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान द्वारा प्रकाशित वैश्विक शिक्षा डाईजेस्ट की रिपोर्ट से उद्घाटित हुआ कि चीन में यह आंकड़ा 26 फीसद, थाईलैंड में 48 फीसद व मलेशिया में 40 फीसद है। इससे जाहिर होता है कि भारत में उच्च शिक्षा में सुधार की रफ्तार धीमी है जबकि शिक्षा पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.98 फीसदी तक जा पहुंचा है। दाखिले के अलावा शोध कार्यों में भी भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। गौर करें तो दुनिया के विकसित देशों में प्रति 10 लाख में 5000 छात्र शोध कार्य में संलग्न हैं। स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या 7000 के आसपास है, जबकि भारत में 250 के आसपास। यह स्थिति उच्च शिक्षा के लिए गंभीर चुनौती है।

यह स्वाभाविक है कि जब उच्च शिक्षा में नामांकन की दर कम होगी तो शोध कार्य करने वाले भी कम होंगे। शिक्षाविदों का मानना है कि अगर भविष्य में भारत को सकल दाखिला अनुपात का लक्ष्य 30 फीसद हासिल करना है और शोध छात्रों की संख्या बढ़ानी होगी वहीं आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ-साथ आठ सौ विश्वविद्यालयों और 35 हजार कॉलेजों की स्थापना करनी होगी। मौजूदा समय में देश में करीब 600 के आसपास विश्वविद्यालय और 25 हजार कॉलेज हैं, लेकिन इनसे उच्च शिक्षा की सुलभता साकार नहीं हो रही है। मौजूदा समय में उच्च शिक्षण संस्थानों के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या है, वह अध्यापकों की कमी और जरूरी संसाधनों का अभाव है। गौर करें तो आज की तारीख में देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में तकरीबन 45 फीसद से 52 फीसद शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें 42 फीसद प्रोफेसरों के पद और 48 फीसद रीडरों के पद रिक्त हैं। इसी तरह 49 फीसदी पद लेक्चरर के पद कॉलेजों में रिक्त पड़े हैं।

एक आंकड़े के मुताबिक, 51 से 70 फीसद शिक्षकों के सहारे पठन-पाठन का काम चलाया जा रहा है। यहीं नहीं भारी पैमाने पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भी कमी है, लेकिन इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के बजाए आउटसोर्स के जरिए काम चलाया जा रहा है। जबकि गौर करें तो प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सवाल उठना लाजिमी है कि जब विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों और जरूरी संसाधनों का अभाव रहेगा तो फिर सुचारू ढंग से पठन-पाठन का कार्य कैसे संपादित होगा? भारत में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कितनी बदहाल है इसी से समझा जा सकता है कि दुनिया के 70 फीसद निरक्षर वयस्क नौ देशों में रहते हैं और उनमें सर्वाधिक 24.74 फीसद भारत में हैं। उच्च शिक्षा के संदर्भ में भारत में शिक्षा पर अत्यंत कम खर्च किया जा रहा है। आज विकसित देशों में उच्च शिक्षा पर जहां कुल बजट का छह से सात फीसद खर्च किया जाता है वहीं भारत आज भी अपनी राष्ट्रीय आय का मात्र 0.42 फीसद धन खर्च करता है। जबकि ज्ञान आयोग द्वारा सुझाव दिया जा चुका है कि शिक्षा पर व्यय को राष्ट्रीय आय के 1.5 फीसदी के बराबर होना चाहिए। समझना कठिन है कि भला इस सीमित बजट के सहारे उच्च शिक्षा के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकेगा और किस तरह भारतीय शैक्षिक संस्थान वैश्विक रैंकिंग में जगह बनाएंगे। उच्च शिक्षा में बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए राष्ट्रीय आय का छह से आठ फीसद खर्च किया जाना जरूरी है।

सैम पैत्रोदा की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर उच्च शिक्षा के प्रति निराशा इसी तरह बनी रही तो 30 फीसद का लक्ष्य हासिल करना बेहद कठिन होगा। आयोग द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि 2015 के अंत तक छात्रों की संख्या दोगनी हो चुकी होगी। गौर करें तो आज की तारीख में यह संख्या तीन गुनी से भी पार जा चुकी है। याद होगा गत वर्ष पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए थे लेकिन उन सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए आयोग ने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों को संबद्ध महाविद्यालयों की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। लेकिन दिलचस्प पहलू यह रहा कि इन सुझावों पर गौर फरमाने के बजाए राज्य सरकारें धड़ाधड़ महाविद्यालयों को खोल रही हैं और उन्हें विश्वविद्यालयों से संबंद्ध कर उन पर अतिरिक्त बोझ लाद रही हैं। आज कुकुरमुत्ते की तरह उग आए इन महाविद्यालयों में न तो प्रशिक्षित शिक्षित हैं और न ही प्रायोगिक कार्यों के लिए जरूरी संसाधन। एक आंकड़े के अनुसार आज 85 प्रतिशत इंजीनियरिंग व 40 प्रतिशत मेडिकल कालेज निजी क्षेत्र के हैं और उन पर सरकारों का किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। लिहाजा महाविद्यालयों का लक्ष्य उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के बजाए अवैध वसूली तक सिमटकर रह गया है, जो स्थिति को बिगाड़ रहा है।

विचार

आंध्र में फिर नया प्रयोग

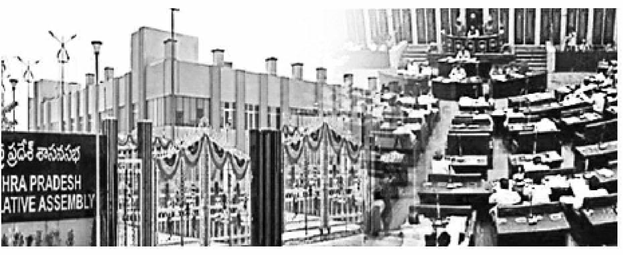

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने राज्य में तीन राजधानी की योजना को आकार देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार जहां इसे विकास से जोड़कर देख रही है, वहीं विपक्ष सीएम को तुगलक करार देने पर अड़ा है। जनता भी सरकार के फैसले पर बंटी है।

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने राज्य में तीन राजधानी की योजना को आकार देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। अमरावती प्रदेश की विधायी राजधानी होगी जबकि विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी व कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी। विधेयक के विधानसभा में पास होते ही प्रदेश सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया है। टीडीपी के 17 विधायक निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई जिसमें कई घायल भी हुए। आंध्र प्रदेश की नई सरकार में यह दूसरा प्रयोग है। जगन सरकार ने इससे पहले पांच उपमुख्यमंत्रियों को नियुक्त कर पूरे देश को हैरान कर दिया था। आंध्र सरकार के तीन राजधानी बनाने के प्रस्ताव से ज्यादा हैरानी इसलिए नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की भी दो राजधानी हैं। आंध्र प्रदेश में नए प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यमंत्री का कार्यालय, राजभवन और सचिवालय समेत कई सरकारी दफ्तर अब विशाखापट्टनम में शिफ्ट होंगे। हाई कोर्ट कुर्नूल में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा अमरावती में रहेगी।

तीन राजधानी वाली अवधारणा के पीछे आंध्र प्रदेश सरकार का तर्क है कि वह प्रदेश के तीनों क्षेत्रों-उत्तरी तट, दक्षिणी तट और रायलसीमा का समान विकास चाहती है। जबकि मुख्य विपक्षी दल टीडीपी विरोध कर रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर समुदाय को ध्यान में रखकर राजधानी के चुनाव का आरोप लगा रही हैं। अमरावती में नायडू समुदाय की आबादी अधिक है तो विजयवाड़ा-गुंटूर क्षेत्र में रेड्डी समुदाय की बहुलता है। चंद्रबाबू नायडू की पिछली सरकार द्वारा अमरावती को प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाना लगभग तय था जिसके लिए 33 हजार करोड़ रुपए की लागत राशि भी मंजूर हो गई थी। देखा जाए तो हर बार आंध्र प्रदेश को सीमाएं बदलने के साथ ही राजधानी से समझौता करना पड़ा है। 1953 में जब आंध्र अलग हुआ जो मद्रास तमिलनाडु में चला गया था। 1956 में आंध्र प्रदेश गठित होने के साथ ही कुर्नूल, हैदराबाद में मिल गया जिससे एक बार फिर प्रदेश को राजधानी के रूप में कुर्नूल खोना पड़ा।

इसी तरह 2014 में तेलंगाना के अलग राज्य बनने पर हैदराबाद तेलंगाना की सीमा में आ गया। अमरावती को राज्य की राजधानी बनाए जाने की दिशा में काम होना था जिसके लिए 33 हजार करोड़ रुपए का बजट तय हुआ। जो भी हो अभी तो आंध्रप्रदेश राजनीति और प्रशासन तंत्र की अभूतपूर्व प्रयोगस्थली बन गया है। चंद्रबाबू नायडू बार-बार अपील कर रहे हैं कि जगन ऐसी गलती न करें तो भाजपा इसे जगन की 'पागलपंती' बता रही है। उधर नागरिकों को यह समझ नहीं आ रहा कि तीन दिशाओं में तीन राजधानियों से राजनीतिक-प्रशासनिक काम कैसे होगा, कैसे आपसी समन्वय बिठाया जाएगा? हालांकि, अभी विधान परिषद में बिल लाना बाकी है, जहां जगन को बहुमत नहीं है। अत: इसे कुछ दिन के विवाद का नाम देना ही सही होगा।

नक्सलियों पर कड़ा प्रहार जरूरी

पिछले कुछ दिनों में सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन चलाकर 10 नक्सलियों को खत्म कर दिया गया। यह बड़ी कामयाबी है। मगर सवाल भी कि आखिर तमाम दावों के बाद भी अब तक नक्सलियों पर लगाम क्यों नहीं कसी जा सकी है। नक्सलवाद खत्म करने के नाम पर जिस तरह के संसाधनों को खर्च किया गया, वह व्यर्थ साबित हो रहा है। नक्सलियों से बातचीत के रास्ते पर चलने को कोई क्यों नहीं तैयार हो रहा है।

पिछले कुछ दिनों में सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन चलाकर 10 नक्सलियों को खत्म कर दिया गया है। इस ऑपरेशन को स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स ने अंजाम दिया था। सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए। यों तो सुरक्षाबलों का दावा है कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की ताकत खत्म हो गई है, वे लगातार सिमट रहे हैं, मगर इस तरह थोड़े-थोड़े अंतराल पर उनके घात लगा कर या फिर सुनियोजित तरीके से हमलों को अंजाम देने से दावे पर विश्वास नहीं होता है। पहली बात यह कि नक्सली योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में सुरक्षाबल अब नाकाम साबित हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले तर्क दिया गया था कि जिन इलाकों में सड़कों आदि का निर्माण हो रहा होता है, वहां नक्सली बड़ी आसानी से बारूदी सुरंग बिछाने में कामयाब हो जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह कहा था कि उनके पास बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं।

यह सही है कि जंगली इलाकों में गश्त करना और नक्सली ठिकानों का पता लगाना सुरक्षाबलों के लिए चुनौतीपूर्ण काम है पर उनके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए जरूरी नहीं कि जंगल की खाक छानी जाए। अत्याधुनिक संचार तकनीक के जरिए भी उनकी टोह ली जा सकती है। लंबे समय से यह दावा किया जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ में तकनीकी मदद से नक्सलियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। नोटबंदी के बाद कहा गया कि इससे उन्हें हथियार और दूसरे साजो-सामान उपलब्ध कराने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे। गृहमंत्री अति शाह ने भी दावा किया है कि नोटबंदी के बाद नक्सलियों व आतंकवादियों की कमर टूट गई है। मगर जब थोड़े-थोड़े अंतराल पर अगर नक्सली हमले हो रहे हैं, तो इससे यही साबित होता है कि सुरक्षाबलों के पास जैसी तैयारी व प्रशिक्षण होना चाहिए, वह नहीं है। दरअसल, लंबे समय से नक्सलियों को हथियार के बल पर दबाने का प्रयास किया जाता रहा है। कुछ साल पहले आदिवासी समुदाय के लोगों को नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार किया गया और सलवा जुडूम नामक अभियान चला कर उम्मीद की गई कि इस तरह नक्सली आंदोलन समाप्त हो जाएगा। पर वह भी नाकाम साबित हुआ।

नक्सली समस्या से पार पाने के लिए बातचीत का जो सिलसिला बनना चाहिए, वह अभी तक नहीं बन पाया। स्थानीय लोगों में भरोसा पैदा करने की जरूरत पहले है। आदिवासियों का विरोध विकास के नाम पर छीनी जा रही उनकी जमीन और जंगल को लेकर है। अगर सरकारें उन्हें समझाने में कामयाब हो जाएं कि विकास किसलिए जरूरी है व इससे उनके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, तो वे शायद नक्सलियों का साथ देना छोड़ देंगे। इसके अलावा, जहां जल, जंगल, जमीन की रक्षा जरूरी है, वहां सरकार को व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करना पड़ सकता है। दमन के सहारे न तो किसी आंदोलन को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है और न ही किसी के मन को बदला जा सकता है। इसलिए नक्सली आंदोलन पर काबू पाने पहले लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। अगर इस दिशा में कामयाबी मिल गई, तो नक्सली ताकतें अपने आप समाप्त हो जाएंगी।

नक्सली हमलों पर काबू पाने के मकसद से विभिन्न राज्यों में अब तक अनेक उपाय आजमाए जा चुके हैं, मगर इस समस्या का हल निकाल पाना चुनौती बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभाव समाप्त करने के मकसद से सलवा जुडूम जैसे प्रयोग किए गए और सुरक्षा बलों को अधिक चौकस बनाने का प्रयास किया गया, मगर इन सबका खास असर नहीं दिखा। इसी तरह बिहार राज्य के जंगली इलाकों में नक्सलियों के दबदबे को खत्म करना कठिन बना हुआ है। सवाल है कि क्यों इस समस्या पर काबू पाने में कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही। नक्सली नेटवर्क को भेदने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष प्रशिक्षण देने, संचार तंत्र को मजबूत करने और खुफिया तंत्र को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। फिर भी स्थिति यह है कि नक्सली संगठनों के पास अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद पहुंच रहे हैं। उनकी योजनाओं का पता लगाना कठिन बना हुआ है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि औरंगाबाद के जंगलों में नक्सलियों से निपटने के लिए वहां की सरकार ने कोबरा नाम से विशेष सुरक्षा दस्ता गठित किया है। वही दस्ता जंगलों में गश्त पर था, तो हमला हो गया। इसमें आईईडी विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। घटना स्थल से एके सैंतालीस, इंसास राइफलें और ग्रेनेड लांचर बरामद हुए। सवाल यह है कि ऐसे साजो-सामान नक्सलियों तक किस तरह पहुंच रहे हैं। नक्सल समस्या पर काबू नहीं पाए जा सकने का बड़ा कारण हमारी सरकारों का उनके साथ बातचीत का व्यावहारिक सिलसिला शुरू न कर पाना और उन्हें विश्वास में न ले पाना भी है। फिर जिस तरह का तालमेल सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों, स्थानीय पुलिस और नागरिकों के साथ बनना चाहिए, वह नहीं बन पा रहा है। नक्सलियों की लड़ाई सैद्धांतिक स्तर पर शुरू हुई थी, मगर अब वह अपनी दिशा खो चुकी है। उनके विभिन्न संगठनों से तालमेल हो चुके हैं, जहां से उन्हें गुरिल्ला प्रशिक्षण और साजो-सामान उपलब्ध हो रहे हैं। यह भी छिपी बात नहीं है कि अनेक जगहों पर नक्सलियों के दबदबे से लोग परेशान हैं। वे जबरन वसूली जैसे कामों में भी शामिल हो गए हैं।

फिर भी सुरक्षा बल उनकी लड़ाई को कमजोर करने में स्थानीय लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं और अवैध रास्तों से उपलब्ध हो रहे साजो-सामान पर नजर नहीं रख पा रहे हैं तो यह उनकी भारी विफलता है। स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही नक्सली प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है, पर सुरक्षा बल प्रायः सख्ती अपना कर उनसे सूचनाएं हासिल करने का प्रयास करते देखे जाते हैं। पूर्वोत्तर के कई विद्रोही संगठन जब बातचीत के जरिए अपना हिंसक रास्ता छोड़ने को तैयार हो सकते हैं, तो नक्सलियों को बातचीत के जरिए समझाना क्यों कठिन होना चाहिए! कई मामले सख्ती के बजाय लचीला रुख अपना कर भी हल किए जा सकते हैं। अगर नक्सल समस्या का बारीकी से अध्ययन कर व्यावहारिक रास्ता निकाला जाए तो हिंसक प्रवृत्ति पर काबू पाना शायद कठिन नहीं होगा। देश में नक्सलवाद पर लगाम कसने के लिए अब तक जो तैयारी दिखनी चाहिए थी, उसका अभाव है। फिर नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार को जिस समर्थन की जरूरत थी, वह भी नहीं मिल पाया है। कई मौकों पर नक्सलवाद के समर्थन में लोग उठ खड़े होते हैं।

पिछले कुछ माह में जिस तरह से देश भर में नक्सलवाद समर्थक लोगों की गिरफ्तारी हुई वह बताती है कि यह समस्या जितनी हम आसान समझ रहे हैं, उतनी है नहीं। अतः सरकार को अब दूसरे विकल्पों पर गौर करना होगा। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार को सीमा पर आंतकियों जैसे ही निपटना होगा। लाख दावों के बाद भी अब तक इस आंतरिक खतरे से निपटने के लिए जवानों को फ्री हैंड नहीं दिया गया है। सीमा पर जवानों को फ्री हैंड देने का असर दिखा है और देश में आतंकी गतिविधियों पर रोक लगी है।

ट्विटर

विकेंद्रीकरण का मतलब यह नहीं होता है कि राजधानी को तीन टुकड़ों में काट दिया जाए और हर क्षेत्र में राजधानी बना दी जाए। तुगलक का राज इससे बेहतर था।

चंद्रबाबू नायडू, पूर्व सीएम

सरकार प्रदेश के उत्तरी तट, दक्षिणी तट और रायलसीमा का समान विकास चाहती है। यह फैसला विशेषज्ञों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

जगन मोहन रेड्डी, सीएम

सत्यार्थ

अपना काम करते रहें

एक बार ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि उनके गांव में सात साल तक पानी नहीं बरसेगा। यह सुनकर सभी गांववासी निराश हो गए और गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन एक किसान को अपने गांव से बेहद प्रेम था, इसलिए वह वहीं डटा रहा। उसने सोचा कि सात वर्ष तक वर्षा तो होनी नहीं है, फिर हल वगैरह का क्या काम? उसने उन्हें उठाकर एक तरफ रख दिया। किसान ने सोचा कि हल वगैरह तो उसने एक तरफ रख दिए, लेकिन यदि सात साल में उन्हें चलाना ही भूल गया तो? इसलिए वह हल उठाकर खेत जोतने लगा। उसने सोचा कि भले ही वर्षा न हो, पर इससे खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। कई दिनों तक वह लगातार खेत जोतता रहा। एक दिन एक बदली वहां से निकली। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां वहां से बिना बरसे ही निकल चुकी थीं, पर यह बदली किसान को खेत जोतते हुए देखकर रुकी और बोली- तूने सुना नहीं कि यहां सात साल तक वर्षा नहीं होगी, फिर तू व्यर्थ में ही खेत को क्यों जोत रहा है? तब किसान बोला-मत बरसो, मैं तो खेत को इसलिए जोतता हूं कि कहीं सात साल में खेत जोतना ही न भूल जाऊं। यह सुनकर बदली हैरान हो गई व सोचने लगी कि कहीं सात साल में मैं भी बरसना न भूल जाऊं। वह बरसने लगी। उसे बरसता देख अन्य बदलियां भी इकट्ठी हो गईं और बदली की बरसना भूलने वाली बात सुन सभी उसका साथ देते हुए बरसने लगीं। इस तरह काम की आदत व श्रम ने भविष्यवाणी को झुठला दिया। तात्पर्य यह कि हम अंधविश्वास में पड़कर किसी भविष्यवाणी को सच न मानें, बल्कि अपने काम पर ध्यान दें। प्रकृति भी उन्हीं लोगों का साथ देती है, जो अपने काम में लगे रहते हैं, उस किसान की ही तरह।

माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया शानदार एप

गणित का कोई भी सवाल चुटकियों में हल करेगा

गणित हमेशा से एक कठिन विषय माना गया है, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो लोग गणित में रुचि लेते हैं, वे गणित के सवाल आसानी से बना देते हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और पहले से तेज हो रहा है। एआई अब बहुत सारे काम करने लगे हैं जैसे कि फोन पर आपको रिप्लाई देना या फिर आपके एक कमांड पर आपकी मां को फोन लगाना। एआई अब उन बच्चों की भी मदद करेगा जिन्हें गणित से डर लगता है और गणित के सवाल को हल करने में परेशानी होती है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित एक एप लॉन्च किया है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट मैथ सोल्वर (Microsoft Math Solver) है। आइए जानते हैं इस एप के बारे में...

माइक्रोसॉफ्ट मैथ सोल्वर एप के फीचर्स

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इस एप को एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए जारी कर दिया है। इस एप में एआई का सपोर्ट है। ऐसे में यह इंटरनेट से ही काम करेगा। इसमें गणित के कई सारे कॉन्सेप्ट और सूत्र अपलोडेड हैं। एप में प्राथमिक अंकगणितीय और द्विघात समीकरणों से लेकर अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट मैथ सोल्वर एप में ड्रॉ करके भी सवाल का हल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्कैन करने और टाइपिंग की भी सुविधा है। इस एप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि छात्रों को किसी सवाल का जवाब स्टेप-बाय-स्टेप में मिलेगा। मैथ सोल्वर एप में वैज्ञानिक कैलकुलेटर भी दिया गया है। इस एप में आप सवाल को हल करने का तरीका भी सीख सकते हैं।

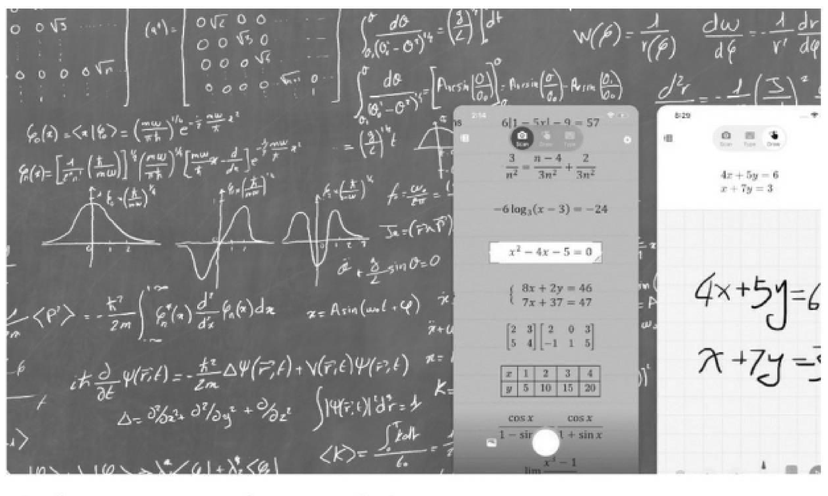

मिलेगा 22 भाषाओं का सपोर्ट

माइक्रोसॉफ्ट ने छात्रों की सहूलियत के लिए इस एप में 22 भाषाओं का सपोर्ट दिया है जिसमें हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, पंजाबी और तमिल जैसी भाषाएं शामिल हैं। इस एप में स्पेनिश रशियन भाषाएं भी हैं। इस एप में वीडियो ट्यूटोरियल और वर्कशीट भी मिलेगी।

क्या-क्या कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट मैथ सोल्वर एप ?

यह एप तमाम तरह के सवालों के जवाब दे सकता है जिनमें अंकगणित, कंप्लेक्स नंबर, लघुत्तम समापवर्तक, फैक्टर्स, प्री-अलजेब्रा, मैट्रिक्स, अलजेब्रा, सीमा और परमुटेशन-कॉम्बिनेशन जैसे विषय के सवाल शामिल होंगे। इस एप को गूगल प्ले-स्टोर और एप्पल के एप से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है।

फेसबुक ने लॉन्च किया नया लॉगिन नोटिफिकेशन फीचर

ऐसे करेगा यूजर्स की मदद

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपने यूजर्स के लिए अब एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से किसी भी नए डिवाइस पर उनके अकाउंट से लॉग-इन किए जाने का नोटिफिकेशन यूजर्स को मिलेगा। ऐसे में किसी थर्ड पार्टी एप पर भी फेसबुक से लॉग-इन करने पर भी यूजर्स को नोटिफिकेशन मिलेगा कि उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन एप के साथ शेयर की जा रही है। ऐसे में यूजर्स का अकाउंट हैक होने और डेटा चोरी का खतरा पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगा।

फेसबुक डिवेलपर ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है, लॉगिन नोटिफिकेशंस का डिजाइन और कंटेंट यूजर्स को रिमाइंड करवाएगा कि उनके डेटा और थर्ड पार्टी एप्स के साथ शेयर की जाने वाली जानकारी पर उनका पूरा नियंत्रण है, यूजर्स आसानी से सेटिंग्स में जाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं और परमिशन में बदलाव कर सकते हैं। फेसबुक का कहना है कि ऐसे नोटिफिकेशंस दो स्थितियों में ट्रिगर होंगे, पहले तो जब कोई यूजर किसी थर्ड पार्टी एप में फेसबुक डीटेल्स की मदद से लॉगिन करेगा और अपना डेटा शेयर करेगा।

नए फीचर्स भी मिलेंगे

साथ ही यूजर के किसी एप में लॉगिन करने के बाद एप को दी गई जानकारी और अकाउंट के लिए एप का एक्सेस एक्सपायर होने पर भी नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। इसी ब्लॉगपोस्ट में फेसबुक की ओर से कहा गया है कि कंपनी 2020 में और भी यूजर कंट्रोल फीचर्स रोलआउट करेगी, जिससे अकाउंट और डेटा से जुड़ी परमिशंस देने और हटाने का ऑप्शन यूजर्स को आसानी से सामने ही मिल जाएगा। इस महीने की शुरुआत में फेसबुक ने अपना प्रिवेसी चेकअप टूल अपडेट किया है और इसमें चार नए फीचर्स एड किए गए हैं।

ऐसे चेक करें एप्स लिस्ट

प्रिवेसी चेकअप टूल प्लैटफॉर्म पर 2014 से ही दिया गया है और इसके नए वर्जन को अब ग्लोबली यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है।

यूजर्स प्रिवेसी चेकअप के लिए फेसबुक की डेस्कटॉप साइट पर बने क्वेश्चन मार्क आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद Apps and websites सेक्शन में यूजर्स को एप के साथ दिख रहे View and edit ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, जिससे वे सिलेक्ट कर सकेंगे कि एप फेसबुक डेटा एक्सेस कर सकता है या नहीं। एप को फेसबुक से हटाने के लिए यूजर्स को Remove पर क्लिक करके कंफर्म करना होगा।

फेसबुक लॉन्च करेगी TikTok जैसा एप Lasso, ऐसे करेगा काम

फेसबुक का शॉर्ट वीडियो एप Lasso आखिरकार सामने आ ही गया है। फेसबुक ने टिकटॉक के मुकाबले में अपने इस लासो एप को पिछले साल लॉन्च किया था, हालांकि यह एप फिलहाल अमेरिका में ही उपलब्ध है, लेकिन अब खबर है कि इस एप को जल्द ही भारत में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल मई तक इस लासो एप को भारतीय यूजर्स के लिए पेश किया जा सकता है। वहीं खबर यह भी है कि वॉट्सएप में लासो के इंटिग्रेशन के लिए भी कंपनी काम कर रही है। टिकटॉक से फेसबुक को मिल रही लगातार कंप्टीशन के बाद कंपनी ने लासो एप को भारत में लॉन्च करने का फैसला लिया है।

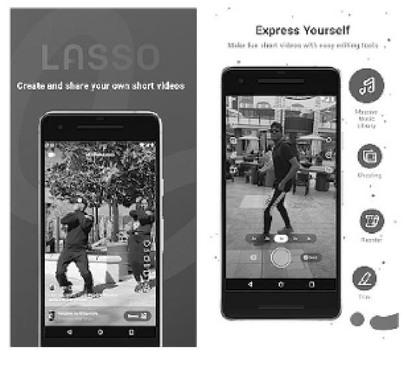

भारत में टिकटॉक एप को आए अभी 27 महीने ही हुए हैं और 25 करोड़ लोगों ने अब तक इस एप को डाउनलोड कर लिया है। इनट्रेकर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लासो एप को इसी साल भारत में लॉन्च किया जाएगा। फेसबुक के सिंगापुर की टीम इस पर काम कर रही है। इस एप के हर एक पहलू पर टीम काम कर रही है। एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लासो एप के प्रमोशन के लिए कंपनी कई इंफ्लूएंसर्स के साथ भी काम कर रही है। बता दें कि लासो एप को पिछले साल अमेरिका में लॉन्च किया गया था और इस एप के वहां लाखों यूजर्स हो चुके हैं। भारत के अलावा लासो एप को इंडोनेशिया जैसे मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा।

लासो एप में आएंगे ये फीचर्स

लासों में म्यूजिक के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अलावा कैमरे में वीडियो एडिटिंग टूल के अलावा कई तरह के इफेक्ट्स मिलेंगे। यूजर्स को ट्रेंड्स और ताजा हैशटैग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

ये पांच सरकारी एप्स आपके स्मार्टफोन में करें डाउनलोड

आएंगे बहुत काम

पिछले कई वर्षों से भारत सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करती आ रही है। सरकार के इन कड़े प्रयासों की बदौलत आज गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर पर कई सारे सरकारी एप्स मौजूद हैं, जिनसे आम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। आज हम आपको सरकार के उन एप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए जानते हैं इन सरकारी एप्स के बारे में-

DigiLocker

डिजिलॉकर एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर पर मौजूद है। इस एप की साइज 7.2 एमबी है। लोग इस एप में जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसमें आप अपने कॉलेज के सर्टिफिकेट भी सेव करके रख सकते हैं। इससे लोगों को हमेशा अपने साथ दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Himaat Plus

सरकार ने हीमात एप को खास महिलाओं की सुरक्षा के लिए पेश किया है। इस एप को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले दिल्ली पुलिस की आधिकारिक साइट पर जाकर अपने-आप को रजिस्टर करना होगा। इसकी खूबी यह है कि अगर यूजर इस एप से मुश्किल परिस्थिति में अलर्ट भेजता है, तो यह जानकारी सीधा दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस को इस अलर्ट में यूजर की लोकेशन और ऑडियो जैसी जानकारी मिलती है। वहीं, इस एप का साइज एंड्रॉयड पर 12 एमबी और आईओएस प्लेटफॉर्म पर 37.2 एमबी है।

M Aadhaar

लोगों के लिए यूआईडीएआई का एम-आधार एप बहुत काम का है, क्योंकि लोगों को इसमें कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। लोग इस एप में आधार कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं। साथ ही लोग अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को भी सुरक्षित रख सकेंगे। वहीं, इस एप का साइज 45 एमबी है। जरूरत पड़ने पर आप इस एप के जरिए भी आधार कार्ड दिखा सकते हैं।

My Gov

सरकार का यह एप बेहद खास है, क्योंकि लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए विभागों और मंत्रालयों को सुझाव दे सकेंगे। वहीं, यह एप गूगल प्ले और एप स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपके पास किसी योजना को लेकर कोई सुझाव या आइडिया है तो आप सरकार को दे सकते हैं।

Voter Helpline

लोगों को इस एप से चुनाव से जुड़ी हर तरह की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही यह एप अपने यूजर्स को कैंडिडेट्स से लेकर नामांकन तक की जरूरी जानकारी देगा। इसके अलावा लोग इस एप के जरिए वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकेंगे। वहीं, इस एप का साइज एंड्रॉयड पर 16 एमबी और आईओएस प्लेटफॉर्म पर 15.6 एमबी है।

कहीं अपका फोन नंबर भी तो नहीं हो रहा है ट्रैक, तो इन चार कोड्स से करें पता

तकनीक के इस दौर में आपको हर एक घर में कई सारे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब इन डिवाइसेज की सुरक्षा यूजर्स के लिए चिंता का विषय बन गई है। क्योंकि आए दिन हैकर्स यूजर्स के डिवाइसेज को ट्रैक करने से लेकर डाटा चोरी करने तक का प्रयास करते हैं। वहीं, स्मार्टफोन यूजर्स को भी जानकारी नहीं होती है कि उनका डिवाइस कोई ट्रैक कर रहा है या फिर उनकी कॉल को कहीं और फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो ऐसे में हम आपके लिए कुछ चुनिंदा कोड्स लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप पता कर सकेंगे कि आपका मोबाइल कहीं ट्रैक तो नहीं हो रहा है?

कोड *#62#

जब कोई आपको कॉल करता है, तो कई बार आपका नंबर नो-सर्विस या नो-आंसर बोलता है। तो ऐसे में आप इस कोड को फोन में डायल कर चेक कर सकते हैं कि किसी ने आपके नंबर को री-डायरेक्ट तो नहीं कर दिया है। इसके अलावा आपका नंबर ऑपरेटर के नंबर पर री-डायरेक्ट भी हो जाता है।

कोड *#21#

अपने फोन में इस कोड को डायल करके आप आसानी से यह जान सकते हैं कि किसी ने आपके मैसेज, कॉल या डाटा को कहीं दूसरी जगह डायवर्ट तो नहीं कर दिया है। अगर आपके कॉल कहीं डायवर्ट किया जा रहा होगा, तो इस कोड की मदद से नंबर सहित पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। वह नंबर भी पता चल जाएगा जिस पर आपका कॉल डायवर्ट किया गया था।

कोड ##002#

यह कोड स्मार्टफोन के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसकी मदद से आप किसी भी फोन के सभी फॉरवर्डिंग को डी-एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कॉल कहीं डायवर्ट हो रहा है तो आप इस कोड को डायल कर डायवर्ट को बंद कर सकते है।

कोड *#*#4636#*#*

इस कोड की मदद से आप अपने फोन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे- फोन में कौन-बैटरी है, वाई-फाई कनेक्शन टेस्ट, फोन का मॉडल, रैम इत्यादि। बता दें कि ये सभी कोड टाल फ्री है, इन कोड को डायल करने पर आपके पैसे नहीं कटेंगे।

अब Google Assistant में मिलेंगे स्मार्ट नए टूल

हाल ही में, हुए कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में नई और एक से बढ़कर एक तकनीकों को दुनिया के सामने रखा गया। गूगल ने भी इस खास कार्यक्रम में अपने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को सबके सामने रखा। कंपनी ने इसके लिए सीईएस में एक डेडिकेटेड बूथ भी ले रखा था, जहां उसने अपनी नई सर्विसेज का डेमो भी दिया। दरअसल, अब गूगल की कोशिश है कि वह गूगल होम और गूगल असिस्टेंट एप से यूजर्स को सभी स्मार्ट होम सलूशन उपलब्ध कराए। कंपनी ने इसके लिए अपने गूगल असिस्टेंट एप में कुछ नए टूल शामिल किए हैं। ये टूल उपयोगकर्ताओं की लाइफ को स्मार्ट और आसान बनाने का काम करेंगे। इन नए टूलों का इस्तेमाल कई चीजों को काफी आसान बना सकता है। इसके अलावा इस बार कंपनी ने उपयोगकर्ताओं की निजता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी एक टूल की सुविधा दी है।

पढ़ेगा लंबे मैसेज और ईमेल

गूगल असिस्टेंट में आप अभी भी ऑडियो बुक्स और ईमेल भी पढ़ सकते हैं। हालांकि, अब गूगल इसमें read longer article aloud फीचर भी एड कर रहा है। असिस्टेंट से किसी पेज को पढ़वाने के लिए यूजर को केवल Hey Google read this page का कमांड देना होगा। इसकी एक और खास बात है कि हर लाइन से साथ यह पेज को नीचे स्क्रॉल भी करता है ताकि यूजर जान सकें कि अभी वे आर्टिकल में किस पैरा या लाइन पर हैं। इसे 42 भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। एंड्रॉयड डिवाइसेज में यह फीचर Read it के नाम से मिलेगा। कंपनी आने वाले कुछ महीनों में इस फीचर को उपलब्ध कराएगी।

गूगल डिवाइस को असिस्टेंट एप से करें लिंक

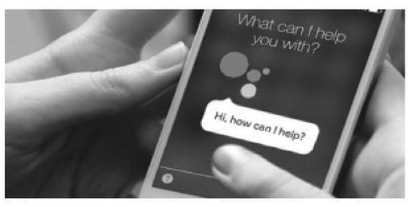

कंपनी की कोशिश है कि वह अब यूजर्स को उन डिवाइसेज को भी गूगल अकाउंट से लिंक करने की सुविधा दे जिन्हें गूगल ने नहीं बनाया है। उदाहरण के तौर पर किसी लाइटिंग कंपनी के स्मार्ट बल्ब को ले सकते हैं। ये स्मार्ट बल्ब गूगल असिस्टेंट से नहीं, बल्कि कंपनी द्वारा दिए गए डेडिकेटेड एप के साथ ही काम करते हैं। गूगल इसी को बदलना चाहता है। इससे यूजर्स को घर में मौजूद नॉन-गूगल स्मार्ट प्रॉडक्ट को गूगल असिस्टेंट से ऑपरेट करने में काफी सहूलियत होगी। अब आप जब भी किसी स्मार्ट डिवाइस को मैन्युफैक्चरर एप से सेट करेंगे तो गूगल आपके फोन पर पुश नोटिफिकेशन देकर बताएगा कि आप डिवाइस को गूगल असिस्टेंट में ऑटोमैटिकली एड कर सकते हैं।

कमांड को करें शेड्यूल

अगर आपके घर में माइक्रोवेव, स्मार्ट टीवी, रोबॉट वैक्युम क्लीनर जैसा कोई स्मार्ट डिवाइस मौजूद है तो आप इसके ऑन और ऑफ होने के टाइम को गूगल असिस्टेंट के नए फीचर Schedule Actions से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके घर में गूगल असिस्टेंट सपॉर्ट वाला स्मार्ट टीवी है तो आप इस टीवी के ऑफ होने के समय को तय कर सकते हैं। इसके लिए आपको Hey Google turn off the tv at10 pm कमांड देना होगा। यह फीचर इस साल 20 से ज्यादा स्मार्ट डिवाइसेज के लिए रोलआउट होने वाला है।

प्राइवेसी कंट्रोल के लिए दो नए ऑप्शन

गूगल असिस्टेंट में यूजर प्राइवेसी को बेहतर करने के लिए दो नए टूल आए हैं। इसमें पहला है कि अगर आपने गलती से गूगल असिस्टेंट को ऑन कर दिया है तो आप इसे कह सकते हैं hey google that wasnt for you (गूगल यह तुम्हारे लिए नहीं था)। ऐसा करने से गूगल असिस्टेंट फिर से बंद हो जाएगा। गूगल अपने असिस्टेंट फीचर से कम्यूनिकेट करने के लिए प्रिवेसी को भी कुछ हद तक एक्सेस करता है। गूगल असिस्टेंट का दूसरा प्रिवेसी टूल इसी को मैनेज करता है। अब आप गूगल असिस्टेंट से Hey Google are you saving my audio data (गूगल क्या तुम मेरा ऑडियो डेटा सेव कर रहे हो) पूछ सकते हैं। इसके बाद गूगल असिस्टेंट आपको प्रिवेसी कंट्रोल के बारे में बताने के साथ ही फोन एप में सेटिंग्स स्क्रीन को ओपन कर देगा, ताकि आप अपने प्राइवेसी प्रिफरेंस में बदलाव कर सकें।

स्मार्टफोन को इस तरह बनाएं स्मार्ट टीवी का रिमोट

रिमोट से टीवी चलाने के दिन अब पुराने हो गए हैं। अब फोन के साथ टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं। ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन से ही स्मार्ट टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके स्मार्टफोन में IR Blaster का होना जरूरी है। यह एक प्रकार का सेंसर होता है जो इंफ्रारेड किरणों के जरिए रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। शाओमी और हुवावे के कई स्मार्टफोन में आईआर की सुविधा मिलती है। इनके जिसके जरिए आप टीवी, एसी, फैन जैसे रिमोट डिवाइसेस को फोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में भी आईआर ब्लास्टर दिया गया है तो आप TV Remote Control एप के जरिए अपने स्मार्टटीवी और इसी प्रकार के दूसरे डिवासेस को कंट्रोल कर सकते हो। जानिए तरीका -

एंड्रॉयड यूजर्स के लिए

- गूगल प्ले स्टोर से TV Remote Control एप डाउनलोड करें।
- अपने एंड्रॉयड फोन और स्मार्ट टीवी को एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जोड़ें।
- स्मार्टफोन में एप ओपन करें और अपने स्मार्ट टीवी के नाम पर टैप करें।

अगर यह तरीका काम नहीं करता

- आपके स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पर एक PIN दिखाई देगा।
- अपने फोन में वह पिन डालें और दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर लें।

IOS यूजर्स के लिए

- एप्पल एप स्टोर से TV Remote Control एप डाउनलोड करें।
- अपने फोन और स्मार्ट टीवी को एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जोड़ें।
- स्मार्टफोन में एप ओपन करें और अपने स्मार्ट टीवी के नाम पर टैप करें।

अगर यह तरीका काम नहीं करता

- आपके स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पर एक PIN दिखाई देगा।
- अपने फोन में वह पिन डालें और दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर लें।

इन एप्स के जरिए फोन को बदलिए रिमोट में

आप अपने स्मार्टफोन को रिमोट बनाने के लिए AnyMote, ASmart, IR Universal और Peel Smart जैसे किसी भी एप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

IRCTC Pay Later एप से ऐसे बुक कीजिए ट्रेन टिकट

पैसे दीजिए बाद में

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) अपने यूजर्स के लिए नई-नई सर्विस लाती रहती है। इसकी एक सर्विस ऐसी भी है, जिसमें आपको रेल टिकट बुक करते समय किसी तरह का पेमेंट नहीं करना होता। टिकट के पैसे आपको बाद में चुकाने की सुविधा दी जाती है। आईआरसीटीसी की इस सर्विस का नाम (बुक नाउ-पे लेटर) है। इसमें आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दिए गए (e-Pay) लेटर ऑप्शन के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। यह सुविधा रिजर्व्ड और तत्काल दोनों तरह के टिकट पर उपलब्ध है। इस सर्विस का यह भी फायदा है कि तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त आपको पेमेंट गेटवे फेल्योर जैसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा।

ऐसे करें इस सर्विस का इस्तेमाल

- सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- टिकट बुक करने के लिए अपने सफर की जानकारी भरें।
- जब आप पेमेंट के पेज पर पहुंचेंगे वहां Pay Later का ऑप्शन दिखाई देगा।
- अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं तो आप ePay Later वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट हो जाते हैं।
- अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP के जरिए ePay Later वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद टिकट के बुकिंग अमाउंट को कंफर्म करना होगा।

कब देनें होंगे पैसे

ePay Later वेबसाइट आपको टिकट बुकिंग के 14 दिन के भीतर पैसे चुकाने का समय देती है। अगर आप 14 दिन में यह पैसा जमा नहीं करा पाते तो यात्रियों को 3.5 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज और साथ में टैक्स भी भरना होगा। इसके अलावा आपका क्रेडिट कम किया जा सकता है जिससे आप अगली बार आईआरसीटीसी की इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor: ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN01927, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

डिप्टी कमिशनर ने नौजवानों को कोचिंग के लिए रजिस्टर होने के लिए किया आह्वाहन

■ जालंधर/प्रभात सूरी

पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई घर -घर रोज़गार स्कीम के अंतर्गत जिला रोज़गार और कारोबार जालंधर की तरफ से नौजवान के कौशल विकास और मानसिक सामर्थ की ओर मज़बूती के लिए कोचिंग सैंटर शुरू किया जा रहा है जिससे उनको अलग -अलग रोज़गार प्राप्ति के लिए दिए जाने वाले इंटरव्यू के लिए उचित ढंग से तैयार किया जा सके।

इस से संबन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से पहले ही नौजवानों को जिला रोज़गार और कारोबार की तरफ से प्लेसमेंट कैंपों और नौकरी मेलों के द्वारा रोज़गार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होने कहा कि कई बार नौजवान पूरी योग्यता होने के बावजूद आत्म विश्वास की कमी करके इंटरव्यू के दौरान अपने हुनर की सही व्याख्या नहीं कर पाते जिस कारण वह रोज़गार प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। उन्होने कहा कि इस कोचिंग सैंटर में इच्छुक नौजवानों को इंटरव्यू के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान की जायेगी। उन्होने कहा कि इस सैंटर में नौजवानों को इंटरव्यू की प्रशिक्षण के लिए माहिरों को तैनात किया जायेगा जिन की तरफ से उन का संपूर्ण विकास किया जायेगा।

श्री शर्मा ने नौजवानों को कहा कि इस कोचिंग सैंटर का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाये और इस कोचिंग सैंटर में प्रशिक्षण के लिए जिला रोज़गार और कारोबार कार्यालय तीसरी मंजिल जिला प्रशासकी कंपलैक्स जालंधर में पहुँच करें। उन्होंने कहा कि घर -घर रोज़गार प्रोग्राम कैप्टन अमरिन्दर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब का नेतृत्व वाली राज्य सरकार का एक अहम प्रोग्राम है जिस का मुख्य उद्देश्य हर नौजवान को रोज़गार उपलब्ध करवाना है। डिप्टी डायरैक्टर सुनीता कल्याण ने कहा कि इस कोचिंग सैंटर से इंटरव्यू से संबन्धित प्रशिक्षण लेने के इच्छुक नौजवान जिला रोजगार और कारोबार कार्यालय या टैलीफोन न 01812225791 और मोबाइल नंबर 8872115120 पर और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।

जवाहर नवोद्धय विद्यालय की रूप रेखा बदलने जायेगी-डिप्टी कमिशनर

विभागों को कमरों, फलडु लाईटों, हाल, छप्पड़ के पुनर्निर्माण के लिए अनुमान तैयार करने के आदेश

■ जालंधर/विजय कुमार

डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने जालंधर से 31 किलोमीटर दौर गाँव तलवंडी माधो में जवाहर नवोद्या विद्यालया की रूप रेखा बदलने की घोषणा की गई है।

श्री शर्मा जो कि जवाहर नवोद्या विद्यालया प्रबंधक समिति के चेयरमैन भी हैं के साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (विकास) श्री कुलवंत सिंह भी उपस्थित ने कहा कि प्रतिष्ठित संस्था में विद्यार्थियों को हर सुविधा प्रदान करने के लिए किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायत, भूमि सुरक्षा विभाग को आदेश दिए कि संस्था में अतिरि1त कमरे बनाओ, बहुमंतवी हाल, शौचालया ब्लाक, नई कुर्सियां, फलडु लाईटें और छप्पड़ के पुर्ननिर्माण के आकलन तैयार किये जायें। उन्होने यह भी घोषणा की कि स्कूल में फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे।

डिप्टी कमिशनर ने सिविल सर्जन जालंधर डा.गुरिन्दर कौर चावला को कहा कि स्कूल में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य जांच के लिए तिमाही मैडीकल कैंप भी लगाए जायें। श्री शर्मा ने पंजाब राज्य पावर निगम लिमटिड को कहा कि स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा को विश्वसनीय बनाने के लिए होस्टल के पास से गुजरती 11 के.वी.लाईन को तुरंत तबदील किया जाये। उन्होने जिला शिक्षा अधिकारी (सकैंडरी) को कहा कि जवाहर नवोद्धया विद्यालया में दाख़िले के लिए अन्य स्कूलों में टैस्ट को विश्वसनीय बनाया जाये। उन्होने यह भी कहा कि स्कूल में सौर ऊर्जा पैनल भी लगाया जायेगा। इस के उपरांत डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल प्रिंसिपल अशोक कुमार के साथ मीटिंग के दौरान विश्वास दिलवाया कि संस्था के मुद्दों को हीयूमन रिर्सोस विभाग के पास उठाया जायेगा। डिप्टी कमिशनर ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल लाने और वापस छोड़ कर आने के लिए नये वाहन को विश्वसनीय बनाया जायेगा।

इस अवसर पर डिप्टी कमिशनर स्मार्ट क्लास रूम, फूड मैस, खेल ग्राउंड, लैबारटरी आदि का निरीक्षण भी किया।

पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के मानवीय सिद्धांतों पर आधारित फलसफे को दर्शाएगी पंजाब की झाँकी

■ चंडीगढ़/चंदन

पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी द्वारा कुल आलम को दिए शाश्वत संदेश 'किरत करो, नाम जपो, वंड छको' को 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए पंजाब सरकार की झाँकी के विषय के तौर पर दर्शाया जायेगा।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गणतंत्र दिवस-2020 के अवसर पर पंजाब राज्य की झाँकी को सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की विचारधारा के साथ-साथ उनके 550वें प्रकाश पर्व सम्बन्धी साल भर चले समागमों को समर्पित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने गुरू साहिब के मानवीय सिद्धांतों पर आधारित फलसफे 'किरत करो', 'नाम जपो', 'वंड छको' को दिखाने की विनम्र कोशिश की है जिसकी आज के समय में भी अहमियत है। उन्होंने कहा कि 'किरत करो' का सिद्धांत ईमानदार साधनों के द्वारा आजीविका कमाने का संदेश देता है जबकि 'नाम जपो' के सिद्धांत के द्वारा परमात्मा के नाम का निरंतर जाप करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसी तरह गुरू साहिब ने अपने तीसरे सिद्धांत 'वंड छको' के द्वारा लोगों को समानता वाले समाज की सृजना के लिए अपनी मेहनत के फल को बाँट कर ग्रहण करने का उपदेश दिया है। श्री गुरु नानक देव जी के सहिष्णुता, शान्ति, सांप्रदायिक सद्भावना, महिला सशक्तिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित संदेश कुल दुनिया के लिए धर्मों में परस्पर साझ का प्रतीक हैं।

ओवैसी ने अमित शाह को दी चुनौती, कहा- सी.ए.ए. पर किसी "दाढ़ी वाले के साथ" करें बहस

हैदराबाद/ब्यूरो

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को बुधवार को चुनौती दी कि वह विपक्ष के नेताओं की बजाय सीएए पर उनके साथबहस करें। नगर निकाय चुनाव से पहले करीमनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए मंगलवार रात हैदराबाद से सांसद ने कहा कि गृह मंत्री ने विपक्षी नेताओं को सीएए पर बहस के लिए आमंत्रित किया है जबकि उन्होंने शाह को उनसे इस कानून पर बहस करने को कहा था। लखनऊ में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में आयोजित एक रैली में शाह ने कहा था कि सीएए को वापस नहीं लिया जाएगा और जो प्रदर्शन कर रहें है वे करते रहें। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को संशोधित कानून पर सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी थी।

शाह ने विपक्ष पर सीएए के खिलाफ लोगों को ''गुमराह'' करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती को सार्वजनिक तौर पर इस पर बहस करने की चुनौती दी थी। शाह की चुनौती पर प्रतिक्रिया देते हुए औवेसी ने कहा, '' मैं यहां हूं.... मेरे साथ बहस करें... इन लोगों के साथ क्यों बहस करनी है... ''दाढ़ी वाले से करो ना''। हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर बहस और बात करेंगे।'' एआईएमआईएम प्रमुख ने केन्द्रीय बजट की 'हलवा' रस्म का जिक्र करते हुए भाजपा पर स्थानों का नाम बदलने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, '' भाजपा ने कहा है कि वह नाम बदलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 'हलवा' शब्द कहां से आया है? यह अरबी शब्द है। यह हिंदी या उर्दू शब्द नहीं है। अब अरबी शब्द भी हटा दें।'' उन्होंने कहा, '' वे (भाजपा) कहते हैं कि वे नाम बदलेंगे। इंशाअल्लाह देश के लोग आपको बदलेंगे। याद रखें मैं हलवा नहीं लाल मिर्च हूं।'' इस बीच, एआईएमआईएम ने तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग से शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे 'फेस रिकग्निशन ऐप' का उपयोग ना करने का अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अन्य उल्लंघनों सहित नागरिकों की निजता का उल्लंघन है।

स्पोर्ट्स

न्यूजीलैंड दौरे से हार्दिक पंड्या का पत्ता कटा, फिटनेस टेस्ट में हुए फेल

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

हाल में फिटनेस टेस्ट में विफल होने वाले हरफनमौला हार्दिक पंड्या के नाम पर न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुनी गयी टीम के लिए विचार नहीं किया गया। यह पता चला है कि पंड्या की फिटनेस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की जरूरतों के मुताबिक नहीं है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए उन्हें बड़ौदा के लिए कम से कम एक घरेलू मैच खेलना होगा। इसके बाद ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू एकदिवसीय श्रृंखला के लिए उनके नाम पर विचार होने की संभावना है। पंड्या ने गेंदबाजी कार्यभार से जुड़ा परीक्षण नहीं दिया था जो पीठ की चोट से वापसी करने वाले गेंदबाज के लिए जरूरी होता है। बड़ौदा के 26 साल के इस क्रिकेटर ने दावा किया था कि वह न्यूजीलैंड दौरे के दूसरे हिस्से के लिए फिट हो जाएंगे लेकिन बीसीसीआई से जुड़े सूत्र कहा कि वह पंड्या का निजी व्यक्तिगत आकलन था। बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि उसे लगा होगा कि वह फिट हो गया। लेकिन उसके ट्रेनर एस रजनीकांत के दावों के उलट वह फिटनेस टेस्ट में विफल हो गया। यह यो-यो टेस्ट नहीं था लेकिन गेंदबाजी फिटनेस के लिए वह कार्यभार परीक्षण में विफल रहे जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है फिटनेस टेस्ट में असफल होना।''

न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया को बताया पावर हाउस

■ आकलैंड/ब्यूरो

न्यूजीलैंड के पूर्व हरफनमौला क्रेग मैकमिलन का मानना है कि मेजबान का सामना भारतीय क्रिकेट टीम के रूप में एक 'पावरहाउस' से है और उसे 'पास' होने के लिये तीन में से दो प्रारूप में जीतना होगा।

भारतीय टीम न्यूजीलैंड में पांच टी20 मैच, तीन वनडे और दो टेस्ट खेलेगी। मैकमिलन ने 'रेडियो स्पोर्ट ब्रेकफास्ट' से कहा ,''यह बड़ी श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, उसके बाद यह पूरा दौरा काफी बड़ा है।''उन्होंने कहा ,''भारतीय टीम पावरहाउस है। टेस्ट, वनडे और टी20 सभी श्रृंखलायें अहम होंगी। न्यूजीलैंड को उत्तीर्ण होने के अंक हासिल करने के लिये तीन में से दो श्रृंखलायें जीतनी होंगी।''

भारत के खिलाफ श्रृंखला का आगाज शुक्रवार को टी20 मैच से होगा। मैकमिलन ने कहा ,''शुरूआत में पांच टी20 मैच होंगे और मुझे पता है कि यह सबका पसंदीदा प्रारूप नहीं है।

इसके बाद अक्टूबर में आस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप होना है लिहाजा ये श्रृंखला अहम है। ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन के बाद हमें जीत की राह पर लौटना होगा।''

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

IELTS • PTE • TOEFL

SPOKEN ENGLISH

TOURIST VISA | STUDY VISA | PR

WORK PERMIT | HOLIDAY PACKAGES

CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE

9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal.

HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com

Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin